संख्या-24/2288/12-2-2014-23/2012

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2014

विषय मृदा स्वास्थ्य का सुदढीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या शो0एवं मृ0सर्वे0/204/वित्तीय स्वीकृति/2014-15 दिनांक 21 जुलाई, 2014 तथा शासनादेश संख्या- 1950/12-2-2014-23/2012 दिनांक 03 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या- 11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरंक्षण-आयोजनागत-102-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 139454 हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 23242 हजार (दो करोड बत्तीस लाख बयालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण फेजिंग करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा:-

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
09-विद्युत देय	9100.00	1516.0
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	115704.00	19284.00
42-अन्य व्यय	14650.00	2442.0
योग-	**139454.00**	**23242.00**

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता हे कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त

http://shasanadesh.up.nic.in